भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या - 568

शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक)

वेतन आयोग की रिपोर्ट

***568. श्री जोस के. मणि:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन में वृद्धि के लिए आंशिक रूप से उनकी सिफारिशों को स्वीकार करके एक के बाद एक वेतन आयोग की रिपोर्टों से सरकार के वित्त/राजकोष पर बोझ बढ़ता रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वेतन आयोग ने औसत या मध्यम दर्जे के निष्पादन को खत्म करने के लिए योग्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेतन आयोगों की सिफारिशों से वेतन में इस प्रकार की आवधिक बढ़ोतरी से राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की ओर से भी इसी प्रकार की मांग उठ रही है जिससे पहले से ही संकटग्रस्त राज्य वित्त पर बोझ बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में वेतन आयोग गठित करने के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए किसी विकल्प पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में श्री जोस के. मणि द्वारा 06 अप्रैल, 2018 के लिए पूछे गए लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 568 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव शुरुआती वर्ष में सामान्यत: अधिक स्पष्ट होता है और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और राजकोषीय गुंजाइश बढ़ती है, यह धीरे-धीरे कम होता जाता है। पिछले केन्द्रीय वेतन आयोग अर्थात् सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय, सरकार ने इसका कार्यान्वयन दो वित्त वर्षों में फैला दिया है। वेतन और पेंशन से संबंधित सिफारिशें 01.01.2016 से लागू की गई थीं, जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशें एक समिति द्वारा जांच के पश्चात् 01.07.2017 से लागू की गई हैं। इससे सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले छठे वेतन आयोग के विपरीत, जिसका बकाया राशि की मद में काफी प्रभाव पड़ा था, इस बार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतन और पेंशन की बकाया राशि के कारण वर्ष 2016-17 में यह प्रभाव पिछले वित्त वर्ष 2015-16 के केवल 2 महीनों का था।

(ख) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.46 में ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया है जो संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम अथवा अपनी सेवा के प्रथम 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति का बेंचमार्क हासिल नहीं कर पाए हैं।

(ग) राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकारों जो केन्द्र सरकार से संघीय रूप से स्वतंत्र हैं, के विशेष कार्यक्षेत्र में आती हैं। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार करना है।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

****